

भारत और यूके ने बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करने का फैसला किया है।

वर्ष 2021 की शुरुआत में COVID-19 महामारी की लहरों के कारण दो दौरे अंतिम क्षणों में रद्द होने के बाद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले सप्ताह दिल्ली का दौरा किया, जहाँ वे व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा पर भारत के साथ अधिक सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध दिखे।

लेकिन वास्तव में यह वास्तविक समझौतों पर आश्चर्यजनक रूप से एक छोटा दौरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापार पर एक फसल समझौता अभी तक ठंडे बस्ते में है, जबकि इस साल ईस्टर (अप्रैल) तक इसकी घोषणा करने की योजना थी। श्री जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर के अंत तक या दीपावली तक पूर्ण एफटीए को पूरा करने की उम्मीद जताई है, ताकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जा सके।

हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित व्यापार प्रतिनिधिमंडल अंतिम समझौते के लिए कितने ट्रेक पर है या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जॉनसन आशावादी लग रहे थे और भारत, यूई और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने एफटीए को तेजी से ट्रेक पर लाने से कोशिश में जुटे हुए हैं। यूके के लिए चिंता का विषय स्कॉच व्हिस्की पर भारतीय टैरिफ को हटाना है, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर कम टैरिफ स्वीकार कर लिया है और यूके भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा बढ़ाने में अधिक लचीलापन दिखा रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद-प्रशांत में रक्षा संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक रूप से सहयोग करने पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर भी चर्चा की है, हालाँकि भारत अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए लिखित रूप से प्रतिबद्ध नहीं दिखा है, जिसका वर्णन श्री मोदी ने ग्लासगो में COP-26 में किया था।

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री जॉनसन ने जिन मुद्दों पर मोदी सरकार संवेदनशील है, उन्हें हल्के में लिया, जैसे कि यूक्रेन और मानवाधिकारों का उल्लंघन। उन्होंने दो सप्ताह पहले अपने विदेश मंत्री की यात्रा के बिल्कुल विपरीत, भारत की स्थिति पर अपनी समझ व्यक्त करते हुए रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत में मानवाधिकारों की चिंताओं पर एक सवाल को खारिज कर दिया।

हालाँकि, उसी दिन एक कारखाने का उद्घाटन करते समय बुलडोजर के साथ खड़े होने पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुकानों और घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने की सरकार की विवादास्पद नई नीति पर विचार कर रहा था। भारत और यूके के अंदर "अतिवाद" का अध्ययन करने के लिए एक उप-समूह स्थापित किया जाना है, जिसका प्रधानमंत्री जॉनसन ने सुझाव दिया था कि खालिस्तानी समूहों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा (जैसा कि नई दिल्ली की इच्छा है), लेकिन इनका उद्देश्य सभी समूहों और व्यक्तियों का मुकाबला करने की है।

बदले में, नई दिल्ली ने आर्थिक भगोड़ों (विजय माल्या, नीरव मोदी) को अभी तक प्रत्यर्पित नहीं करने के मुद्दे पर अधिक जोर नहीं देने का फैसला किया है।

नई दिल्ली और लंदन दोनों को निकट भविष्य में उन समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए और अधिक ठोस प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि "रोडमैप 2030", जिस पर 2021 में अंतिम शिखर सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई थी, के तहत अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट- एफटीए) क्या है?

- ➔ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का इस्तेमाल देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है।
- ➔ एफटीए दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच की व्यवस्था है जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत है।
- ➔ एफटीए, आम तौर पर वस्तुओं में व्यापार (जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं में व्यापार (जैसे बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) को कवर करता है।
- ➔ एफटीए अन्य क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर कर सकता है।
- ➔ एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत, बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

भारत-यूके रोडमैप 2030 क्या है?

- ➔ यह रोडमैप अगले दस वर्षों में दोनों देशों के बीच साझेदारी की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है।
- ➔ रोडमैप 2030 तक यूके-भारत व्यापार के मूल्य को दोगुना करने और भविष्य के मुक्त व्यापार सौदे के लिए पूर्व-वार्ता के पहले चरण में तेजी लाने के लक्ष्य के साथ, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक 'संवर्धित व्यापार साझेदारी' की शुरुआत करता है।
- ➔ 2005 में औपचारिक 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' समझौते के बाद यह पहला समझौता है।
- ➔ दोनों देश समुद्री डोमेन जागरूकता पर एक नए सहयोग पर सहमत हुए हैं। इसमें समुद्री सूचना साझाकरण पर नए समझौते, गुडगांव में भारत के सूचना फ्यूजन सेंटर (Information Fusion Centre) में शामिल होने के लिए निमंत्रण शामिल हैं।
- ➔ दोनों देश लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर काम कर रहे हैं।
- ➔ दोनों देश भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान की आवश्यकता पर सरकार से सरकार के सहयोग का निर्माण करने पर सहमत हुए हैं।
- ➔ साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, G20, UNFCCC, WTO, IMF, World Bank आदि में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं।
- ➔ वे देशों के थिंक टैंकों के बीच ट्रैक 5 और ट्रैक 2 संवाद को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही वे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ढाँचे में जुड़ाव को बढ़ावा देंगे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत-यूके रोडमैप 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह रोडमैप अगले दस वर्षों में दोनों देशों के बीच साझेदारी की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करता है।
2. हाल ही में (2022) इस रोडमैप 2030 में भारत तथा ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा है।
3. इसके तहत यूके-इंडिया यंग एंटरप्रेन्योरशिप फोरम (UK-India Young Entrepreneurship Forum) लॉन्च किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

- (क) केवल 1 (ख) केवल 2
(ग) 1 और 3 (घ) 2 और 3

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of India-UK Roadmap 2030:-

1. This roadmap outlines the ambitions of the partnership between the two countries over the next ten years.
2. Recently (2022) Australia is also associated along with India and Britain in this roadmap 2030.
3. Under this, the UK-India Young Entrepreneurship Forum will be launched.

Which of the above statement(s) is/are not correct?

- (a) 1 only (b) 2 only
(c) 1 and 3 (d) 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत और ब्रिटेन को संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बीच सामंजस्य की कमी को पहचानने की जरूरत है। भारत-ब्रिटेन संबंधों में व्याप्त चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान हेतु उपाय सुझाएँ। (250 शब्द)

Q. India-Britain needs to recognise the lack of harmony between different strands of the relationship. While mentioning the challenges prevailing in India-UK relations, suggest measures to solve them. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।